

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

07 मार्च, 2020

“दर में कटौती से मनोभाव को बढ़ावा मिल सकता है लेकिन फेड रेट में कटौती होने के बाद बाज़ार की प्रतिक्रिया के रूप में यह क्षणिक साबित होगा।”

COVID-19 द्वारा नुकसान पहुँचाई गई आर्थिक भावना को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मंगलवार को दरों में 50 आधार अंकों की भारी कटौती ने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकिंग को बाधित किया है। यहाँ तक कि विश्लेषकों ने इस प्रश्न पर कि क्या मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया सही रणनीति है, तर्क दिया है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2008 के बाद से सबसे बड़ी दर में कटौती का पालन करने का दबाव महसूस हो रहा है।

ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के केंद्रीय बैंकों ने पहले ही दरों में कटौती कर दी है जबकि अन्य जैसे बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक कटौती करने पर विचार कर रहे हैं।

प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति

मौद्रिक नीति के साथ वायरस के कुप्रभावों के विरुद्ध आर्थिक रक्षा की वास्तविक प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में, भारत में फोकस भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया की ओर मुड़ गया है। आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद में 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड (उपज) बुधवार को 0.12% तक गिर गई लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकल्प क्या है? अन्य देशों के विपरीत, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी, MPC) की स्थापना के बाद भारत में कानूनी ढाँचा ऐसा है कि आरबीआई एकतरफा दरों को समायोजित नहीं कर सकता है।

दरों में कटौती करने से पहले एमपीसी को स्थिति पर विचार करना होगा और इस तरह की कटौती को अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन पर आधारित होना होगा। लेकिन क्या दर में कटौती सही प्रतिक्रिया है?

वायरस के प्रसार की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहला प्रभाव व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए आया व्यवधान है। यह वायरस चीन में पहले से ही सेल फोन के घटकों से लेकर ड्रग्स और ऑटो घटकों तक के उत्पादों की आपूर्ति बाधित कर चुका है। दुनिया भर में फैक्ट्रियाँ आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से कई समस्याओं का सामना कर रही हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अनुमान लगाया है कि वायरस के प्रभाव के कारण वैश्विक व्यापारिक निर्यात 50 बिलियन डॉलर से कम हो सकता है। 19.48 ट्रिलियन डॉलर (2018) के कुल वैश्विक व्यापारिक निर्यात की तुलना में यह आँकड़ा काम प्रतीत होता है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक शुरुआत भी हो सकती है।

मौद्रिक नीति माँग के झटके को संबोधित करने के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन जब बात आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को संबोधित करने की आती है तब यह असरदार साबित नहीं होती। लोग दर में कटौती के कारण अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं लेकिन अगर सिनेमाघरों, यात्रा स्थलों और सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मूवी थिएटर और मॉल चलेंगे ही नहीं, तो वे खर्च क्या करेंगे?

आरबीआई पर दबाव

दर में कटौती खर्च करने की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, लेकिन यह अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा दर में कटौती के बाद बाज़ार की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण क्षणिक भी हो सकती है। स्वीडिश केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर अन्ना ब्रेमन ने कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण दर में कटौती करने पर सवाल उठाया है, जिनके अनुसार एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति स्थिति में सुधार नहीं कर सकती है।

एमपीसी की विवशता को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरबीआई फरवरी में दर में की गई कटौती की तरह ही इस बार भी कटौती कर सकता है। इस प्रकार, हम एक बार फिर से केंद्रीय बैंक को लंबी अवधि के रेपो संचालन की एक और किश्त की घोषणा करते हुए देख सकते हैं, जोकि 1 लाख करोड़ का है जिसे फरवरी में घोषित किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि बैंक 5.15% की रेपो दर पर तीन साल के फंड तक पहुँच हासिल करेंगे, जो बाज़ार दर से काफी कम है।

लेकिन यह संदेहास्पद है कि इनमें से कोई भी उपाय आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस बहुत ही गलत समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में वापसी के संकेत दिखा रही थी। इसका प्रभाव एक से अधिक मोर्चे पर महसूस किया जाएगा। फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग चीनी इनपुट पर अपनी उच्च निर्भरता को देखते हुए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

निर्यात में संभावित गिरावट

बड़ी समस्या निर्यात में गिरावट से हो सकती है, जिसका जीडीपी का 20% हिस्सा है। यदि विकसित विश्व वायरस के कारण मंदी में चला जाता है, तो पेट्रोलियम, वस्त्र, चमड़ा, जवाहरात और आभूषण तक के उत्पादों के निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

बेशक, तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण तेल आयात बिल कम होगा। इसका मुद्रास्फीति पर भी एक उदार प्रभाव हो सकता है, लेकिन यदि विकसित दुनिया मौद्रिक विस्तार पर जोर देती है तो यह केंद्रीय बैंक के लिए सिरदर्द का कारण बनेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में उपलब्ध उच्चतर रिटर्न की तलाश में आने वाले हॉट मनी की अंतर्वाह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

लेकिन संकट के बावजूद, अवसर मौजूद हैं। अल्पावधि में आर्थिक विकास को नुकसान होता है, लेकिन अगर घरेलू उद्योग और सरकार अपने कार्यों को सही से कार्यान्वित करते हैं तो दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं का नए निवेशों के माध्यम से स्थानीयकरण किया जा सकता है और भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में आगे बढ़ सकता है।

COVID-19 संकट ने केवल उस सबक को रेखांकित किया है जिसे वैश्विक निगमों ने सीखा था जब अमेरिकी और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया था, जहाँ इन्होंने महसूस किया था कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन के लिए वैकल्पिक विकल्पों की आवश्यकता है। भारत उस भूमिका को ग्रहण करने के लिए सबसे आगे खड़ा है। हालाँकि, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे नीति-निर्माता और उद्योगपति इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार कीजिए:

1. तेल की कीमतों में वृद्धि
2. पर्यटन में कमी
3. इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित
3. जनांकिकीय लाभांश पर सकारात्मक प्रभाव

कूट:-

- (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 3 और 4

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the effects of Corona virus on Indian economy:

1. Increase in oil prices
2. Reduction in tourism
3. Electronic and automobile sector affected
4. Positive effect on demographic dividend

Code:-

- (a) 1, 2 and 3 (b) 2 and 3
(c) 2, 3 and 4 (d) 1, 3 and 4

नोट : 06 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 के वैश्विक स्वास्थ्य के इतर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के द्वारा मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया जाना क्या एक तर्कपूर्ण कदम माना जा सकता है? भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

Could the US Federal Reserve's change in monetary policy be considered a logical step in view of the effects of corona virus or COVID-19 on the global economy other than global health? What will be its impact on India? (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।